स्मार्ट शहरों के चयन की प्रक्रिया

प्रत्येक महत्वाकांक्षी शहर 'सिटी चैलेंज' में एक स्मार्ट सिटी के रूप में चयन के लिए प्रतिस्पर्धा करेगा। चयन प्रक्रिया के दो चरण हैं। संबंधित मुख्य सचिवों को संख्या का संकेत देने के बाद, जैसा कि ऊपर पैरा 8 में उल्लिखित है, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा निम्नलिखित चरणों का कार्य किया जाएगा:-

1.1 प्रतियोगिता का स्टेज 1: राज्यों द्वारा शहरों का चयन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की पूर्ववर्ती स्थिति और स्कोरिंग मानदंडों के आधार पर और इसे आबंटित कुल संख्या के अनुसार संभावित स्मार्ट शहरों चयन शुरू करता है। प्रतियोगिता का पहला चरण अंतर राज्यीय है, जिसमें राज्य के शहर पूर्ववर्ती स्थिति और निर्धारित स्कोरिंग मानदंड पर प्रतिस्पर्धा करेंगे। संभावित शहरों द्वारा प्रतियोगिता के पहले दौर में सफल होने के लिए इन शर्तों को पूरा किया जाना है और उच्चतम स्कोरिंग करने वाले संभावित स्मार्ट शहरों का चयन किया जाएगा और चैलेंज के स्टेज 2 में भाग की सिफारिश की जाएगी। पूर्ववर्ती शर्तें और प्रपत्र दिशा निर्देशों का अनुबंध 4 में दिए गए हैं। प्रपत्रों में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा भेजी गई जानकारी राज्य मिशन निदेशक द्वारा मूल्यांकन किया जाना है और मूल्यांकन के अनुमोदन के लिए राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एचपीएससी) के समक्ष रखा जाना है। राज्य एचपीएससी की संरचना दिशा निर्देशों के पैरा 13 में दी गई है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निर्धारित तिथि तक शहरी विकास मंत्रालय को सिफारिश की गई स्मार्ट शहरों की सूची के रूप में प्रतियोगिता के पहले दौर में सफल होने वाले शहरों को भेजा जाएगा (मुख्य सचिवों को लिखे गए पत्र में संकेत दिया जाना है)। राज्य सरकार को प्रपत्र (अनुबंध 3 में दिए गए) को भरना होगा और सिफारिश की गई सूची के साथ भेजना होगा। इसके बाद शहरी विकास मंत्रालय 100 स्मार्ट शहरों की सूची की घोषणा करेगा।

1.2 प्रतियोगिता का स्टेज 2: चयन के लिए चैलेंज का दौर

प्रतियोगिता के दूसरे चरण में, संभावित 100 स्मार्ट शहरों में से प्रत्येक 'सिटी चैलेंज' में भाग लेने के लिए अपने प्रस्ताव तैयार करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण स्तर है क्योंकि प्रत्येक शहर के स्मार्ट सिटी के प्रस्ताव (एससीपी) में चुना गया मॉडल शामिल होने की संभावना है, चाहे वो रिट्रोफिटिंग या पुनर्विकास

या ग्रीनफील्ड विकास या उनका मिश्रण हो, और इसके साथ ही इसमें स्मार्ट समाधान के साथ एक पैन शहर आयाम शामिल है। एससीपी में शहर निवासियों और अन्य हितधारकों के साथ हुए विचार-विमर्श की रूपरेखा तैयार किया जाएगा कि एससीपी में निहित मिशन को कैसे पूरा किया जाएगा और महत्वपूर्ण रूप से निजी भागीदारी को आकर्षित करने के लिए राजस्व मॉडल सहित स्मार्ट सिटी योजना के वित्तपोषण के लिए प्रस्ताव क्या है। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा पेशेवरों के सलाह पर एससीपी के लिए मूल्यांकन का मानदंड तैयार किया गया है और इसे उनके प्रस्ताव तैयार करने के लिए शहरों के मार्गदर्शन के रूप में कार्य करना चाहिए। आवेदन के साथ भेजे जाने वाले मानदंड और दस्तावेज दिशानिर्देश के अनुबंध-4 में दिए गए हैं।

1.3 एक निर्धारित तिथि तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले संकेत को इन सभी 100 शहरों के लिए शहरी विकास मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। इनका मूल्यांकन एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषजों, संगठनों और संस्थानों का एक पैनल शामिल होगा। चैलेंज के पहले दौर के विजेताओं को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित किया जाएगा। इसके बाद, जबिक जीतने वाले शहर अपने शहर स्मार्ट बनाने पर कार्रवाई शुरू करेंगे, जिनका चयन नहीं होगा वे दूसरे दौर में विचार के लिए अपनी एससीपी में सुधार लाने पर कार्य शुरू करेंगे। एससीपी के स्वरूप और चैलेंज के पहले दौर के परिणामों के आधार पर, शहरी विकास मंत्रालय दूसरे दौर को शुरू करने से पहले उनके प्रस्तावों के उन्नयन के लिए संभावित स्मार्ट सिटी को सहायता प्रदान करने के लिए हैंडहोल्डिंग का फैसला कर सकते हैं।

स्मार्ट शहरों के चयन के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं।

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वितिरत स्मार्ट सिटी की संख्या के अनुसार चरण-1 के मानदंडों के आधार पर संभावित स्मार्ट सिटी का चयन करने के लिए सभी राज्य सरकारों को पत्र भेजना। यह अंतर राज्य प्रतियोगिता का पहला चरण है।



राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिक्रिया के आधार पर, संभावित 100 स्मार्ट शहरों की सूची की घोषणा की गई है। उसके बाद अखिल भारतीय प्रतियोगिता का दूसरा चरण शुरू होता है।



प्रत्येक संभावित स्मार्ट सिटी सलाहकार (शहरी विकास मंत्रालय द्वारा तैयार एक पैनल से) और हैंडहोल्डिंग बाहरी एजेंसी (प्राप्त विभिन्न प्रस्ताव जैसे विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, जीईएफ, यूएसटीडीए, जेआईसीए, डीएफआईडी, एएफडी, केएफडब्ल्यू, संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट) की सहायता से अपना प्रस्ताव तैयार करता है।



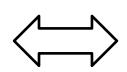
निर्धारित तिथि तक स्टेज-2 के प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया। विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा मूल्यांकन।



चयनित शहरों की घोषणा- दौर 1 के स्मार्ट सिटी।



चयनित शहरो द्वारा एसपीवी का गठन किया गया और उनके एससीपी का कार्यान्वयन शुरू किया गया। डीपीआर, निविदाएं आदि तैयार करना।



अन्य शहरों द्वारा चैलेंज के अगले दौर के लिए अपने प्रस्ताव में सुधार करने के लिए तैयारी करते हैं।

चैलेंज स्टेज 1: प्रत्येक राज्य द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली पूर्व शर्तें और दस्तावेज पूर्व शर्तें

- 1. स्मार्ट सिटी बनाने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता (प्रपत्र 1, भाग-3),
- 2. स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पैरास्टेटल निकाय, शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी), संगठन और शहरी विकास प्राधिकरण (यूडीए) को मिलाकर इंटर विभागीय कार्य दल का गठन किया जाएगा। (प्रपत्र 1, भाग-4),
- 3. स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चयनित नगर परिषद का संकल्प, (फॉर्म 2, भाग-5) और
- 4. शहर विकास प्राथमिकताओं पर निवासियों के साथ परामर्श किए गए (प्रपत्र 2, भाग-6)

स्कोरिंग मानदंड

संभावित स्मार्ट शहरों के लिए स्कोर करने और उच्चतम स्कोर के साथ शहरों के नाम शहरी विकास मंत्रालय को भेजने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रयोग की जाने वाली स्कोरिंग मानदंड नीचे दिए गए है ताकि उनके चयन हेतु चुनौती देने के लिए स्टेज 2 में भाग लिया जा सके।

1. मौजूदा सेवा स्तर

- जनगणना 2011 के बाद वृद्धि का प्रतिशत या घरेलू स्वच्छता शौचालयों की संख्या पर स्वच्छ
 भारत आधार, जो भी कम हो (प्रपत्र 2, भाग-1) 10 अंक,
- ॥. प्रतिक्रिया के साथ संचालित ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली को वापस शिकायतकर्ता को
 भेजा जा रहा है। (प्रारूप 2, भाग-2) (हां/नहीं) 5 अंक,
- iii. कम से कम पहली मासिक ई-न्यूजलेटर को प्रकाशित किया गया। (प्रपत्र 2, भाग-3) (हां/नहीं) 5 अंक, और
- iv. वेबसाइट पर पिछले दो वितीय वर्षों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से परियोजना-वार नगर निगम के बजट व्यय जानकारी देना। (प्रपत्र 2, भाग-4) - (हां/नहीं) - 5 अंक।

2. संस्थागत प्रणाली/क्षमता

i. सेवा प्रदान करने में देरी के लिए प्रतिपूरक जुर्माना लगाना शुरू किया गया (हाँ/नहीं) (प्रपत्र 2, भाग 7)- 5 अंक, और

ा. पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2012-15) के दौरान आंतिरिक उत्पन्न राजस्व का कुल संग्रह (जैसे कर, शुल्क, प्रभार) में बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई गई है। (प्रपत्र 2, भाग 8) (हां/ नहीं) - 10 अंक।

3. स्व-वित्तपोषित

- i. पिछले महीने तक यूएलबी द्वारा वेतन का भूगतान (प्रपत्र 2, भाग-9) 5 अंक,
- ii. वित्तीय वर्ष 12-13 की लेखाओं की लेखा परीक्षा (प्रपत्र 2, भाग-10) 5 अंक,
- iii. यूएलबी बजट के लिए कर राजस्व, शुल्क और उपयोगकर्ता शुल्क, किराया और अन्य आंतरिक राजस्व स्रोतों के अंशदान का प्रतिशत (2014-15 में वास्तविक) - (प्रपत्र 2, भाग 11) - 10 अंक, और
- iv. स्थापना की प्रतिशतता और जल की आपूर्ति का रखरखाव लागत, जो पिछले वित्त वर्ष (2014-15) के दौरान पानी की आपूर्ति के लिए एकत्र उपयोगकर्ता प्रभारों से पूरा किया गया है -(प्रपत्र 2, भाग 12) - 10 अंक

4. पिछले रिकॉर्ड और सुधार

- वित्त वर्ष (2014-15) के दौरान पूंजीगत कार्य के लिए इस्तेमाल प्रयुक्त आंतिरक राजस्व स्रोतों
 (स्वयं उत्पन्न) के बजटीय धनराशि का प्रतिशत (प्रपत्र 2, भाग 13) 10 अंक,
- ग्राप्त शहर-स्तर जेएनएनयूआरएम सुधारों का प्रतिशत (प्रपत्र 2, भाग 14) छह (6) यूएलबी
 स्तर सुधार के लिए 10 अंक, और
- iii. पूरा किए गए जेएनएनयूआरएम परियोजनाओं का प्रतिशत, जिसे मूल मिशन अविध (2012 तक) के दौरान मंजूर किया गया था (प्रपत्र 2, भाग 15) 10 अंक।

दस्तावेज

प्रपत्र जिसके तहत राज्यों को शहरी स्थानीय निकाय से प्रस्ताव हुआ है और जिसमें उन्हें शहरी विकास मंत्रालय को भेजना है, नीचे दिए गए हैं।

- 1. प्रत्येक राज्य द्वारा चयनित शहरों की सूची (प्रपत्र 1, भाग -1)।
- 2. प्रत्येक चयनित शहर द्वारा पूरा किए गए चयन के मापदंड की घोषणा (प्रपत्र 1, भाग-2)। इस प्रपत्र को प्रत्येक चयनित शहर को प्रस्तुत किए जाने की जरूरत है।
- 3. स्मार्ट सिटी बनाने के लिए राज्य सरकार की वचनबद्धता (प्रपत्र 1, भाग -3)
- 4. अंतर-विभागीय टास्क फोर्स के गठन का आदेश (प्रपत्र 1, भाग-4)

नगर आयुक्त/यूएलबी प्रमुख के हस्ताक्षर के तहत प्रत्येक चयनित शहर द्वारा प्रपत्र 1 के समर्थन में राज्य मिशन निदेशक को अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगा। (फार्म 2)

प्रपत्र 1 (शहरी विकास मंत्रालय को राज्य द्वारा भेजे जाने के लिए)

₹	ज्य	ा का	ा न	TЪ	Γ:

आवंटित शहरों की संख्याः

भाग 1: प्रत्येक राज्य द्वारा चयनित शहरों की सूची।

क्र.सं.	शहर का नाम	शहर की जनसंख्या	पूर्व शर्ती	से संतुष्ट		
			1	2	3	4
			हाँ/नहीं	हाँ/नहीं	हाँ/नहीं	हाँ/नहीं

भाग 2: प्रत्येक चयनित शहर से प्राप्त स्कोर का विवरण*

चयनित शहर का नामः

क्र.सं.	मानदंड	कुल स्कोर	स्कोर प्राप्त
1	घरेलू स्वच्छता शौचालयों की संख्या पर जनगणना	10	
	2011 या स्वच्छ भारत आधार में वृद्धि (जो भी कम		
	हो)।		
2	प्रतिक्रिया के साथ संचालित ऑनलाइन शिकायत	5	
	निवारण प्रणाली को वापस शिकायतकर्ता को भेजा जा		
	रहा है।		
3	कम से कम पहली मासिक ई-न्यूजलेटर को प्रकाशित	5	
	किया गया।		

4	वेबसाइट पर पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से परियोजना-वार नगर निगम के बजट व्यय की जानकारी देना।	5
5	सेवा प्रदान करने में देरी के लिए प्रतिपूरक जुर्माना लगाना।	5
6	पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2012-15) के दौरान आंतरिक रूप से सृजित राजस्व (उदाहरण के लिए कर, शुल्क, प्रभार) का संग्रह।	10
7	पिछले महीने तक शहरी स्थानीय निकाय द्वारा वेतन का भुगतान	5
8	वित्तीय वर्ष 12-13 के लिए खातों की लेखा परीक्षा	5
9	कर राजस्व, शुल्क और उपयोगकर्ता शुल्क, किराया और अन्य आंतरिक राजस्व स्रोतों का योगदान प्रतिशत।	10
10	जल आपूर्ति की रखरखाव लागत तथा स्थापना का प्रतिशत	10
11	वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान पूंजीगत कार्य के लिए प्रयुक्त आंतरिक राजस्व स्रोत (स्वयं उत्पन्न) का प्रतिशत योगदान	10
12	शहर-स्तर जेएनएनयूआरएम सुधारों का प्राप्त प्रतिशत	10
13	जेएनएनयूआरएम के तहत मार्च, 2012 तक मंजूर परियोजनाओं के पूरा होने का प्रतिशत।	10
	कुल	100

^{*}इस प्रपत्र को प्रत्येक चयनित शहर के लिए भरे जाने की जरूरत है।

भाग 3: राज्य सरकार की ओर से वचनबद्धता

मैं इसके द्वारा पुष्टि करता हूं कि राज्य (नाम) पूरी तरह से ____(नाम) शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

भाग 4: अंतर्विभागीय कार्य दल के गठन के आदेश

स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पैरास्टेटल निकाय, यूएलबी, यूडीए को मिलाकर एक अंतर-विभागीय कार्य दल का गठन करने का सरकारी आदेश संलग्न है।

मैं इसके द्वारा पुष्टि करता हूं कि मैंने जानकारी को सत्यापित कर दिया है और यह सत्य और सही है। एचपीएससी द्वारा दिनांक ------ को आयोजित अपनी बैठक में शहर के नाम को अनुमोदित कर दिया गया है

(प्रमुख	सचिव/सचिव	(शहरी	विकास)
		_ राज्य	सरकार।

प्रारूप 2 - स्कोर कार्ड

(शहरी स्थानीय निकाय द्वारा राज्य को भेजे जाने के लिए)

ा नामः

राज्य का नामः

मौज्दा सेवा स्तर

भाग 1: स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित स्वच्छ शौचालयों में वृद्धि।

	उपलब्धि	उपलब्धि 7.5 से	उपलब्धि 5 से	उ पलब्धि
	>10%	10% के बीच।	7.5% के बीच।	<5%
	10 अंक	7.5 अंक	5 अंक	० अंक
जनगणना 2011 में वृद्धि का				
प्रतिशत या घरेलू स्वच्छता				
शौचालयों की संख्या पर				
स्वच्छ भारत आधार (जो भी				
कम हो)				

भाग 2: प्रचलित ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली

	हाँ (5 अंक)	नहीं (0 अंक)
प्रतिक्रिया के साथ ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली को		
प्रचालनशील बनाकर वापस शिकायतकर्ता को भेजा जा रहा है।		

भाग 3: मासिक ई-न्यूजलेटर

	हाँ (5 अंक)	नहीं (0 अंक)
कम से कम पहली मासिक ई-न्यूजलेटर प्रकाशित		
किया गया।		

भाग 4: इलेक्ट्रॉनिक सक्षम परियोजना-वार नगर निगम के बजटीय व्यय के बारे में जा	र म जानकार	5 बार	ক	ट्यय	बजटाय	क	ानगम	नगर	पारयाजना-वार	सक्षम	डलक्टानिक	भाग ४
--	------------	-------	---	------	-------	---	------	-----	--------------	-------	-----------	-------

	हाँ (5 अंक)	नहीं (0 अंक)
वेबसाइट पर पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए		
परियोजना-वार नगर निगम के बजटीय व्यय के बारे		
में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जानकारी दी गई।		

भाग 5	: निर्वाचित नगर	परिषट	द्र का संव	कल्प					
	दिनांक	_ का	संकल्प	सं.	 (अंग्रेजी/हिंदी/अन्य	संस्करण)	की	एक	प्रति
संलग्न	है।								

भाग 6: दिनांक, विशिष्ट एजेंडा और शहर के निवासियों के साथ आयोजित वार्ड विचार-विमर्श में उपस्थिति लोगों की संख्या के साथ तालिका।

क्र.सं.	दिनांक	एजेंडा	वार्ड नं.	भाग लेने वाले लोगों की संख्या

संस्थागत प्रणाली/क्षमता

भाग 7: सेवा प्रदान करने में देरी के लिए प्रतिपूरक जुर्माना की उगाही

	हाँ (5 अंक)	नहीं (0 अंक)
सेवा प्रदान करने में देरी के लिए जुर्माना प्रतिपूरक की उगाही की शुरूआत		

भाग 8: पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2012-15) के दौरान आंतरिक रूप से सृजित राजस्व (उदाहरण के लिए कर, शुल्क, प्रभार) के कुल संग्रह की बढ़ती प्रवृति।

		वर्ष	हाँ (१० अंक)	नहीं (0 अंक)	
पिछले तीन वित्तीय वर्षी	2012-13	2013-14	2014-15		
(2012-15) के दौरान					
आंतरिक रूप से सृजित					
राजस्व (उदाहरण के लिए					
कर, शुल्क, प्रभार) के कुल					
संग्रह की बढ़ती प्रवृत्ति।					

<u>स्व-वित्तपोषित</u>

भाग 9: वेतन का भुगतान

	हाँ (5 अंक)	नहीं (0 अंक)
पिछले महीने तक यूएलबी द्वारा वेतन का भुगतान		

भाग 10: लेखाओं की लेखापरीक्षा

	हाँ (5 अंक)	नहीं (O अंक)
वित्तीय वर्ष 12-13 तक लेखाओं की लेखापरीक्षा		

भाग 11: कर राजस्व, शुल्क और उपयोगकर्ता शुल्क, किराया और अन्य आंतरिक राजस्व के स्रोतों का प्रतिशत अंशदान

	यूएलबी	बजट	यूएलबी बजट	यूएलबी बजट से	यूएलबी
	से >	50%	से 35% से	20% से 35% के	बजट से
	योगदान		50% के बीच	बीच योगदान।	20% से
			योगदान।		कम योगदान
	10 अंक		7.5 अंक	5 अंक	० अंक
	10 01-1		7.5 514	3 314	0 01-1
यूएलबी बजट प्राप्तियों में					
कर राजस्व, शुल्क और					
उपयोगकर्ता शुल्क, किराया					
और अन्य आंतरिक राजस्व					
के स्रोतों का प्रतिशत					
अंशदान (2014-15 में					
वास्तविक)।					
वास्तविक)।					

भाग 12: जल आपूर्ति की रखरखाव लागत तथा स्थापना का प्रतिशत

	>	80%	60%	से	80%	40%	से	60%	<	40%
	उपयोग	कर्ता	के		बीच	के		बीच	उपयोग	ाकर्ता
	प्रभार	से	उपयोग	कर्ता		उपयो	गकर्ता	प्रभार	प्रभार	से आने
	आने	वाले	प्रभार	से	आने	से	आने	वाले	वाले	
	रखरखा	व।	वाले र	खरख	ाव।	रखर	<u>बाव।</u>		रखरख	ाव।
	10 अंक	-	7.5 3	iक		5 अंव	ফ		० अंक	-
पिछले वित्तीय वर्ष के										
दौरान पानी की आपूर्ति										
के लिए उपयोगकर्ता										
शुल्क संग्रह के माध्यम										

से	पूरा	किए	गए
ओएं	डएम	लागत	का
प्रतिः	शत।		

पिछले रिकॉर्ड और सुधार

भाग 13: वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान पूंजी निर्माणकार्य के लिए उपयोग किए हुए आंतरिक राजस्व स्रोतों (स्व-मृजित) का प्रतिशत योगदान

	पूंजी	निर्माण	पूंजी	ſ	नेर्माण	पूंजी	निम	र्गण	कार्य	पूंजी	निर्माण
	कार्य	के लिए	कार्य	के	लिए	के	लिए	5 %	र से	कार्य	के लिए
	20%		10%	से	20%	10%	5	के	बीच	5% 3	योगदान
	योगट	ान	के बी	च यो	गदान	योग	दान				
	10 3	iक	7.5 3	भंक		5 3	ांक			० अं	ফ
वित्तीय वर्ष 2014-15 के											
दौरान पूंजी निर्माणकार्य											
के लिए उपयोग किए											
हुए आंतरिक राजस्व											
स्रोतों (स्व-सृजित) का											
प्रतिशत योगदान											

भाग 14: शहर-स्तर जेएनएनयू आरएम सुधार।

	प्राप्त सुधारों का	प्राप्त सुधारों	प्राप्त सुधारों का	प्राप्त सुधारों
	100%	का 90%	80%	का < 80%
	10 अंक	7.5 अंक	५ अंक	० अंक
प्राप्त शहर-स्तर जेएनएनयूआरएम				
स्धारों* का प्रतिशत।				
3				

^{*}चक्र वी रिकॉर्ड 31.3.2014 के अनुसार

भाग 15: जेएनएनयू आरएम के अंतर्गत मार्च, 2012 तक मंजूर परियोजनाओं का पूरा होना।

	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण परियोजनाओं
	परियोजनाओं	परियोजनाओं	परियोजनाओं	के लिए 80% से
	के लिए 100%	के लिए 90%	के लिए 80%	कम
	10 अंक	7.5 अंक	5 अंक	० अंक
जेएनएनयूआरएम				
परियोजनाओं का प्रतिशत**				
पूरा हो गया, जिन्हें मूल				
मिशन की अवधि के दौरान				
(मार्च, 2012 तक) मंजूर				
किए गए थे				

^{** 31.3.2014} के अनुसार राज्य से प्राप्त समापन प्रमाण पत्र के अनुसार।

में इसके द्वारा पुष्टि करता हूं कि मैंने इस प्रारूप में प्रस्तुत जानकारी को सत्यापित किया है जो मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है।

(नगर आयुक्त/यूएलबी के प्रमुख, पैरास्टेटल)

चुनौती स्तर 2: मानक सामग्री और सांकेतिक सारणी

4.1 <u>मानक</u>

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एससीपीएस का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ मानक नीचे दिए गए हैं।

क्र.सं.	मानक	स्कोर
शहर स्त	स्र्यांकन मापदंड	30
1	कार्यान्वयन की विश्वसनीयता	
क.	पिछले तीन वर्षों में, निर्माण योजना को मंजूरी देने के लिए दिए गए औसत	
	समय, संपत्ति कर का आकलन और संग्रह में वृद्धि, पानी की आपूर्ति के लिए	
	घरेलू नल और उपयोगकर्ता प्रभारों के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक संस्थाओं	
	की संचालन क्षमता में कैसे सुधार हुआ है? एक महीने में अनुसूचित आउटेज?	
	एक महीने में अनिर्धारित आउटेज? क्या एनआरडब्ल्यू/यूएफडब्ल्यू और	
	एटीएंडसी/टीएंडडी के घाटे में कमी आई है? ग्रिड आधारित बिजली के द्वारा	
	शामिल आबादी की प्रतिशतता में वृद्धि? वार्षिक मांग की प्रतिशतता के रूप में	
	संपत्ति कर संग्रह। वाहनों के स्थान पर नज़र रखने, परिवेश प्रकाश सेंसर, आदि	
	जैसे लागत प्रबंधन के उपाय।	
ख.	पिछले तीन वर्षों में यातायात की भीड़ में सुधार हुआ है - औसत यातायात की	
	गति, औसत प्रयोगकर्ता समय, पैदल यात्री सुविधाओं में वृद्धि, सार्वजनिक	
	परिवहन में सुधार, और निम्नतर प्रयोगकर्ता दूरी?	
ग.	क्या सूचना प्रौद्योगिकी और संचार (आईटीएंडसी) के प्रयोग से प्रशासनिक दक्षता	
	में सुधार हुआ है, (1) पदाधिकारियों की उपस्थिति दर्ज करना और उसके	
	परिणाम स्वरूप बेहतर उपस्थिति, (2) लोगों के साथ दो तरह से संचार स्थापित	
	करना, (3) वैधानिक दस्तावेजों तक परेशानी मुक्त पहुँच बनाने के लिए ई-शासन	
	का प्रयोग, (4) डैशबोर्ड्स विकसित करना जो एनालिटिक्स और दृश्य को	
	एकीकृत करता है जिससे प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि के साथ ही नागरिकों को	

	जानकारी मिलती हैं,						
ਬ.	वर्तमान वार्षिक मांग के % के रूप में जल एवं सीवरेज उपयोगकर्ता प्रभार						
	एकत्रित। क्या किफायती आवास के लक्ष्यों की प्राप्ति की स्थिति क्या रही है –						
	स्लम बस्तियों को पुनर्विकसित, उन्नत किया गया और आवास उपलब्ध करा						
	गई?						
2.	शहर का विजन और रणनीति						
क.	अपने शहर के रहने योग्य बनाने के लिए स्थानीय लोगों की जरूरतों, आकांक्षाओं						
	और इच्छाओं का लक्ष्य कैसे पूरा होगा?						
ख.	सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार लाने और स्थानीय नागरिकों के जीवन की						
	गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग कर						
	इस विजन को कैसे पूरा किया जाएगा?						
ग.	विजन का विवरण मुख्य आर्थिक गतिविधि, स्थिरता और समग्रता पर प्रभाव को						
	संक्षेप में कैसे प्रस्तुत करेगा?						
प्रस्ताव स्तर के मूल्यांकन का मापदंड							
3	प्रस्ताव का प्रभाव						
क.	इन लक्ष्यों को नागरिक परामर्श के माध्यम से अभिज्ञात किए गए विजन से						
	कैसे पूरा किया जाएगा? क्या लक्ष्यों को मात्रात्मक परिणामों से जुड़ा गया हैं						
	और सभी परिणामों को सूचीबद्ध किया गया है? क्या लक्ष्य वितरणयोग्य हैं?						
ख.	क्या पैरा 6.2 में दिए गए सभी आवश्यक तत्वों को प्रस्ताव में शामिल किया						
	गया हैं? क्या सभी तत्वों और निर्धारित लक्ष्यों के लिए संकेतक तैयार किए गए						
	हैं? पैरा 3.1(i-vii) में दिए गए स्मार्ट सिटी के कितनी विशेषताओं को शामिल						
	किया गया है और मात्रा निर्धारित की गई है?						
ग.	अभिज्ञात किए गए कितने लक्ष्यों को उद्देश्यों के साथ जोड़ा गया है और						
	संकेतकों पर विशिष्ट जानकारी और गतिविधियों के लिए उद्देश्यों को मैप किया						

	गया है?	
ਬ.	क्या 3(ग) के उद्देश्यों के लिए निर्धारित लक्ष्य नागरिक जरूरतों के अनुरूप है	
	जैसाकि परामर्श में अभिज्ञात किया गया था?	
ङ.	प्राथमिक आर्थिक आधार और शहर के रोजगार पर प्रस्ताव के प्रभाव क्या है?	
	(उदाहरण के लिए रोजगार और आय में वृद्धि)।	
च.	प्रस्ताव कितना समावेशी है? इस प्रस्ताव से गरीबों को क्या लाभ और हानि हुई	
	₹?	
4	किफायती लागत	
क.	क्या प्रस्ताव में कार्यान्वयन योजना शामिल हैं? क्या कार्यान्वयन योजना की	
	तैयारी के दौरान विभिन्न प्रौद्योगिकी और शहरी नियोजन के विकल्प शामिल है	
	जो अभिज्ञात किए गए परिणामों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं? क्या	
	शहरों में विकल्पों में से एक का चयन किया गया है? क्या कार्यान्वयन योजना	
	में 'स्मार्ट' घटक है, जहां "स्मार्टनेस" कम से अधिक करने को संदर्भित है, जो	
	अधिक संसाधन कुशल तरीके से कुछ किया जा रहा है (संसाधन का पर्याय	
	समय, धन, प्राकृतिक संसाधनों आदि हो सकता है)? क्या प्रस्ताव में अधिकांश	
	मौजूदा अवसंरचना का बनाया गया है? कार्यान्वयन योजना में पहल के	
	अभिसरण की क्या सीमा है? क्या कार्यान्वयन योजना में केवल हार्डवेयर खरीद	
	अनुबंध के बजाय समाधान सेवाओं के ठेकों को शामिल किया गया है? क्या	
	सामान्य प्रौद्योगिकी विनिर्देशों को प्रस्तावित किया गया है?	
ख.	क्या वित्तपोषण योजना तैयार कर ली गई है? क्या इस परियोजना के लिए वित	
	पोषण के विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जा रहा है?	
	- केन्द्र सरकार स्मार्ट सिटीज़ के अनुदान % हिस्सा	
	- निजी क्षेत्र का % हिस्सा	
	- राज्य/शहरी स्थानीय के संसाधनों का % हिस्सा	
L		

	- पूरक केन्द्र सरकार की योजनाओं में % हिस्सा।					
	- अन्य स्रोतों का % हिस्सा।					
ग.	क्या प्रस्ताव आर्थिक रूप से टिकाऊ है? (उदाहरण के लिए ओएंडएम लागत की					
	प्रस्तावित व्यवस्था)।					
घ.	क्या वित्तीय मान्यताओं को सूचीबद्ध किया गया है? वित्तीय मान्यताओं को देखते					
	हुए, समय-सीमा के भीतर प्रस्ताव कैसे संभव है?					
ਭ.	प्रस्ताव में कोई भी मितव्ययी इंजीनियरिंग और किए गए नागरिक नवाचार?					
	सार्वजनिक सेवा वितरण की गुणवता में सुधार करने के लिए क्राउड सोर्स्ड					
	आईटी उपायों के माध्यम से नागरिक नवाचारों की संख्या?					
5	नवाचार और अनुमापकता					
क.	क्या नागरिकों के साथ परामर्श में सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान और चयन किया					
	गया है? यदि हां, तो वे कितनी अच्छी तरह से अनुकूल हैं?					
ख.	क्या पूरे शहर के लिए या अन्य शहरों के लिए परियोजना अनुमापीय है?					
ग.	आपदाओं से पर्यावरण और लचीलापन पर प्रस्ताव के प्रभाव क्या है? (उदाहरण					
	के लिए रिट्रोफीटिंग में गर्म द्वीपों को कम करना)।					
घ.	क्या क्षेत्र आधारित और पैन-सिटी के घटनाक्रम में किसी भी स्मार्ट समाधान का					
	इस्तेमाल किया गया है जैसाकि पैरा 2.5 के विस्तृत सूची के दिया गया है?					
	क्या प्रत्येक प्रौद्योगिकी उपाय के लिए प्रौद्योगिकी विनिर्देश विकल्पों की जांच की					
	गई है और नागरिकों के साथ साझा किया गया है? वांछित परिणामों में इसका					
	क्या प्रभाव होगा?					
6	अपनाई गई प्रक्रिया					
क.	व्यापक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से प्रत्येक कदम के सह-सृजन के लिए					
	प्रक्रिया का विवरण (विचार, रणनीति, कार्यान्वयन तंत्र और वित्तीय समाधान):					

	-नागरिक	
	-समाज के कमजोर वर्गों (विकलांग, बच्चे, बुजुर्ग आदि) वार्ड समितियां और क्षेत्रीय सभाएं।	
	-महत्वपूर्ण नागरिकों समूह (संघ, संगठन और संस्थान जैसे स्थानीय वाणिज्य चैम्बर)।	
ख.	नागरिक परामर्श के दौरान सामाजिक मीडिया, समुदाय, मोबाइल गवर्नेंस इस्तेमाल कैसे किया गया है?	
ग.	रणनीति और योजना में विपरीत "आवाज" को कैसे शामिल किया गया है?	

4.2 सामग्री की सांकेतिक सारणी

आवेदन पत्र के संबंध में विस्तृत निर्देश और प्रस्ताव के प्रारूप अलग से जारी किए जाएंगे। सामग्री की एक संकेतात्मक सारणी नीचे दी गई है

- i. क्षेत्र और प्रस्ताव पहचान रेट्रोफिटिंग, पुनर्विकास और हरित क्षेत्रों का विकास।
- ii. प्रस्ताव का दायरा और उद्देश्यों।
- ііі. प्रस्ताव की अवधारणा।
- iv. प्रस्ताव का विकास।
- v. कार्यान्वयन ढांचा।
- vi. प्रस्तावित वित्तपोषण विकल्प और संस्थागत ढांचा।
- vii. प्रस्ताव का चरण और समय सीमा।
- viii. लाभ और प्रभाव का आकलन।

प्रस्तावों की तुलना के लिए वर्ष-वार माईलस्टोन और परिणामों को प्रस्ताव में निम्नलिखित सारणी के रूप में दी जानी चाहिए।

लक्ष्यः

उद्देश्य और	कार्यनिष्पादन	आधाररेखा	मिशन	वितीय वर्ष के लिए			
क्रियाकलाप	संकेतक	(तिथि xx	लक्ष्य	डेढ वर्ष के लिए		ढाई वर्ष के लिए	
		के रूप में)		आधारभूत	उपयोग	आधारभूत	उपयोग
				प्रगति	की जाने	प्रगति	की जाने
					वाली		वाली
					धनराशि		धनराशि
उद्देश्य 1							
गतिविधि १							
गतिविधि 2							
गतिविधि 3							
उद्देश्य 2							
गतिविधि १							
गतिविधि 2							
गतिविधि 3							

(नोटः परियोजना के पूरा होने तक, हर छमाही में प्रत्येक परियोजना के लिए उपरोक्त जानकारी प्रदान किया जाना है)।